भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3600
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: परम्परागत कृषि विकास योजना
3600. श्री थरानिवेंथन एम एस:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के मुख्य उद्देश्य और लक्षित लाभार्थी सहित इसका परिदृश्य क्या हैं;
(ख) पीकेवीवाई के अंतर्गत तमिलनाडु के अरानी निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में किसानों के बीच जैविक खेती और संवहनीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं;
(ग) सरकार किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि किसानों, विशेषकर ग्रामीण और सीमांत समुदायों के किसानों को पीकेवीवाई से संबंधित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध हो;
(घ) क्या पीकेवीवाई के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) अथवा स्थानीय संगठनों के साथ भागीदारी स्थापित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और
(ङ) सरकार की कृषि उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और भागीदार किसानों की समग्र आजीविका के संबंध में पीकेवीवाई के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने की योजना बना रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क)और (ख): परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण प्रमाणन और क्लस्टर दृष्टिकोण में विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। पीकेवीवाई योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

- प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु अनुकूल सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना जो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने और बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को न्यूनतम करने को सुनिश्चित करते हैं;

- सतत एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से किसानों की कृषि की लागत को कम करना जिससे प्रति इकाई भूमि पर किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि हो।
- मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का निरंतर उत्पादन करना।
- पर्यावरण के अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से पर्यावरण की रक्षा करना।

- पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन (पीजीएस) के माध्यम से व्यक्तिगत और छोटे किसान समूहों को प्रमाणन तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना जो किसी भी योजना द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करने के लिए जैविक क्लस्टर (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा) बनाना है। पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3 वर्ष के लिए 31500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15000 रुपये/हेक्टेयर/3 वर्ष किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे खेत और खेत से बाहर जैविक इनपुट के लिए प्रदान किए जाते हैं। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्यवर्धन के लिए 3 वर्ष के लिए 4500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये/हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्ष के लिए 9000 रुपये/हेक्टेयर की दर से सहायता भी प्रदान की जाती है।

तमिलनाडु सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य सरकार चेन्नई जिले को छोड़कर पूरे राज्य में पीकेवीवाई योजना को कार्यान्वित कर रहा है, 1057 क्लस्टर बनाए गए हैं, जो 37886 किसानों को शामिल करते हुए 32940 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। अरणी निर्वाचन क्षेत्र में जैविक खेती के अंतर्गत 81 किसानों को शामिल करते हुए 60 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 3 क्लस्टर बनाए गए हैं।

(ग) पीकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों के लिए 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें किसानों के लिए प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट आयोजित करती हैं।

(घ): जी हां, पीकेवीवाई के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्थानीय संगठनों और अन्य स्टेकहोल्र्स के साथ साझेदारी स्थापित की गई है और इसका विवरण इस प्रकार है: -

सेवा प्रदाताओं (एसपी) के रूप में एनजीओ की भागीदारी। एसपी के रूप में, एनजीओ किसानों को संगठित करते हैं, समूह बनाते हैं और जैविक खेती की तकनीकों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे जैविक खेती के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायता करते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों (आरसी) की भूमिका: सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन और अन्य स्थानीय संगठनों को जैविक प्रमाणीकरण के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) के तहत आरसी के रूप में राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र में पीजीएस-सचिवालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। वे प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और जैविक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

(ड.): इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, पीजीएस-इंडिया पोर्टल पर जैविक प्रमाणीकरण और अनुपालन का डेटा रखा जाता है, जिससे प्रमाणित किसानों और समूहों की पारदर्शिता और वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित होती है।

****